प्रेसनोट

पिथौरागढ़–30.09.13(सूवि),

प्रभावितों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना सरकार का दायित्व है और धारचूला, मुनस्यारी, झूलाघाट सहित सभी प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से लेकर हल करने के साथ प्रभावितों को हर संभव मदद दे रही है। उक्त बात आज विकास भवन सभागार में आपदा राहत समिति की बैठक लेते हुए प्रदेश के नियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, युवा कल्याण एवं जनपद प्रभारी मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कही।

उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास हेतु सरकार कटिबद्ध है और कई स्थानों पर भूमि का चयन कर उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी भूमि उपलब्ध होने के बाद आपदा प्रभावित गांवों का पुर्नवास किया जायेगा, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास हेतु सरकार स्तर पर कार्यवाही गतिमान है, जैसे ही भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी, लोगों का पुर्नवास प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उन्होंने धारचूला से उपर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पैदल रास्तों के बाद घोड़े खच्चरों के लिए रास्तों को ठीक करने हेतु लोनिवि को तेजी लाने और मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधीक्षण अभियंता लोनिवि को निर्देश दिये कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों से माईग्रेशन होने तक पैदल रास्ते घोड़े–खच्चरों हेतु तैयार कर लें। श्री अग्रवाल ने जिलाधिकारी को बीआरओ से भी सड़क मार्गो को खोलने में तेजी लाने के निर्देश जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यो में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जायेगी और कार्यो में पारदर्शिता व गुणवत्ता खराब पाये जाने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को झूलाघाट के आपदा प्रभावितों की एक सप्ताह में सामुहिक बैठक कर उनको दी जाने वाली सभी अतिरिक्त अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने आपदा से जिनके भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और किराये पर रह रहे हैं उनको समय पर किराया उपलब्ध कराने के निर्देश भी बैठक में दिये। श्री अग्रवाल ने बताया कि अनुगृह अनुदान के रूप में शासन से उपलब्ध 1175 लाख को जनपद से भी अवमुक्त कर प्रभावितों में वितरित कर दिया गया है तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण को मिले 1200 लाख को वितरित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त 950 लाख को विकासखंडवार धारचूला को 500 लाख, मुनस्यारी को 300 लाख, पिथौरागढ़ को 7 लाख, गंगोलीहाट को 3.25 लाख, डीडीहाट को 3.25 लाख तथा बेरीनाग को 2.25 लाख की धनराशि वितरित कर दी गई है। उन्होंने आपदा राहत समिति को अवगत कराया कि अभी तक मृतकों, लापता लोगों, घायलों आदि को मुआवजे की धनराशि वितरित कर दिया गया है। उन्होंने आपदा प्रभावित समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि हर हालत में आपदा प्रभावितों की पूर्ण सहायता की जायेगी।

बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत सुनीता देवी, विधायक मयूख महर, विधायक नारायण राम आर्य, अध्यक्ष नगरपालिका जगत सिंह खाती, जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल, मुख्य विकास अधिकारी डा.आनन्द श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी धारचूला प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी मुनस्यारी एके शुक्ला, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य आन सिंह, मनोहर टोलिया, खीमराज जोशी आदि उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़–30.09.13(सूवि),

राज्य के विकास के लिए तत्पराता, संजीदगी से कार्य होने के साथ कार्यो में पारदर्शिता, गुणवत्ता बनाये रखें। उक्त बात आज विकास भवन सभागार में जिला योजना की बैठक लेते हुए प्रदेश के नियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, युवा कल्याण एवं जनपद प्रभारी मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कही। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्ययोजना प्रस्तुत करने से पहले स्थानीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों से भी कार्यो पर चर्चा करें और समय–समय पर विधायकों को भी कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करायें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013–14 की 5384 लाख की जिला योजना में अतिआवश्यकीय कार्यो को प्राथमिकता प्रदान करना सुनिश्चित करें।

श्री अग्रवाल ने कहा कि कार्यो में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को विशेष ध्यान रखें और विभागीय कार्यो को कार्यदायी संस्था पर न छोड़कर स्वयं भी उसका समय–समय पर निरीक्षण हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला योजना राज्य के विकास की नींव होती है और विकास की किरण यहीं से प्रारम्भ होती है इसलिए अधिकारी इसे संजीदगी से लें और अति आवश्यक कार्यो को प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यो को गति दें। उन्होंने अधिकारियों को कठोर संदेश दिया कि किसी भी कार्य में गुणवत्ता व पादर्शिता खराब पाये जाने पर अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यो का ब्यौरा क्षेत्रीय विधायकगणों को उपलब्ध कराने के साथ उन्हें कार्यो का स्थलीय निरीक्षण भी करायें।

उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए परियोजना प्रबंधक उरेडा को बांटी जा रही सोलर लालटेन में गुणवत्ता बनाये रखने और सभी तहसीलों में सोलर लालटेन बटे सुनिश्चित करें। उन्होंने छूटे हुए परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सोलर लालटेन बांटने के निर्देश भी बैठक में दिये। चिकित्सा विभाग की समीक्षा में मंत्री ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विधायकों का सहयोग लेने, पशुपालन विभाग को कार्यो की सूची विधायकों व जिला योजना समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराने, माध्यमिक शिक्षा को अधूरे भवनों को पूर्ण करने हेतु तेजी से प्रयास करने के निर्देश दिये।

उन्होंने पर्यटन अधिकारी को बड़े स्तर पर पर्यटक स्थलों को विकसित करने हेतु योजना प्रस्तुत करने, साहसिक खेलों हेतु कुमाऊं मंडल विकास निगम को कार्यदायी संस्था बनाने के साथ साहसिक गतिविधियों हेतु उन्हें 12 लाख की धनराशि जिला योजना से अवमुक्त करने के निर्देश दिये। जिला उद्योग केंद्र को विभिन्न योजनाओं के प्रशिक्षण हेतु एक्सपर्ट को आमंत्रित करने, कृषि विभाग को हर ब्लाक के गांवों में मृदा परीक्षण हेतु प्रेरित करने और इस हेतु बृहत स्तर पर अभियान चलाने के साथ ग्राम प्रधानों का सहयोग लेने के निर्देश मंत्री ने दिये। दुग्ध विभाग को दुग्ध रूट बढ़ाने और दुग्धशाला का जनप्रतिनिधियों को निरीक्षण कराने, युवा कल्याण को खेल गतिविधियों में तेजी लाने के साथ अगले वित्तीय वर्ष में जिला योजना में और अधिक धनराशि प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। लोक निर्माण विभाग को अधूरे कार्यो को तेजी से पूर्ण करने, विद्युत विभाग को क्षतिग्रस्त 193 खंभे और 23 खराब ट्रांसफार्मरों को तेजी से बदलने के निर्देश बैठक में मंत्री ने दिये।

बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत सुनीता देवी, विधायक मयूख महर, विधायक नारायण राम आर्य, विधायक विशन सिंह चुफाल, अध्यक्ष नगरपालिका जगत सिंह खाती, जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल, मुख्य विकास अधिकारी डा.आनन्द श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी बीएल राणा, उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, एके शुक्ला सहित समिति के सदस्य मनोहर टोलिया, कैलाश खड़ायत, समिति के अन्य सदस्य, खीमराज जोशी, अन्य जनप्रतिनिधि, आदि उपस्थित थे।